बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 25 ● नई दिल्ली ● शनिवार 01 नवम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में 22 वर्षीय अपराधी की गोली मारकर हत्या

नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में सात आपराधिक मामलों में शामिल 22 वर्षीय एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना 30 अक्टूबर की रात करीब 10.40 बजे हुई जब गोलीबारी की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर पुलिस को इलाके में जामा मस्जिद के पास एक व्यक्ति गोली लगने से घायल पड़ा मिला। उसे तत्काल जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान जाफराबाद के निवासी मिस्बाह के रूप में हुई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, अपराध स्थल से साक्ष्य एकत्र करने के लिए फॉरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया गया है।

सरदार पटेल भी हैरान हो जाते..., लौह पुरुष की जयंती पर कांग्रेस ने बीजेपी-आरएसएस पर साधा निशाना

नई दिल्ली।

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर कांग्रेस ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि उनके निस्वार्थ नेता भी हैरान हो जाते, अगर उन्हें पता चलता कि उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। खुद पटेल के शब्दों में, इस विचारधारा ने ऐसा माहौल बनाया, जिससे महात्मा गांधी की हत्या जैसी खौफनाक घटना संभव हो सकी। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश कहा, खासकर 2014 से दो लोगों का समूह (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह) और उनका तंत्र 2014 से इतिहास को बेधड़क तोड़-मरोड़कर पेश कर रहा है। रमेश ने एक्स पर लिखा, आज जब कृतज्ञ राष्ट्र सरदार पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है, हमें याद रखना चाहिए कि 13 फरवरी 1949 को जवाहर लाल नेहरू ने गोधरा में सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण किया था, जहां उन्होंने अपना वकालत का करियर शुरू किया था। इस अवसर नेहरू का भाषण दोबारा पढ़ना चाहिए, ताकि उनकी तीन दशकों से अधिक की मजबूत और गहरी साझेदारी को समझा जा सके। रमेश ने कहा, सरदार पटेल की 75वीं जयंती के मौके पर नेहरू ने कहा था कि पटेल ने अपने लंबे और उल्लेखनीय सेवा रिकॉर्ड के बावजूद

देश की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाला और उन्होंने राष्ट्रीय गतिविधियों में उनके साथ तीस वर्षों का साथ साझा किया। इन वर्षों में उठापटक और बड़ी घटनाओं के बीच पटेल एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे, जिनसे बड़ी संख्या में लोग मार्गदर्शन की उम्मीद रखते थे। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि 19 सितंबर 1963 को तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने संसद भवन और चुनाव आयोग कार्यालय के पास नई दिल्ली के प्रमुख गोल चौराहे पर सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण किया था। नेहरू भी उस समय मौजूद थे और उन्होंने मूर्ति पर भारत की एकता के शिल्पकार का सरल लेकिन शक्तिशाली शब्द चुना। उन्होंने याद दिलाया कि 31 अक्तूबर 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की शताब्दी वर्ष समापन समारोह की अध्यक्षता की और उनकी अनेक उपलब्धियों और योगदानों को व्यापक रूप से याद किया। रमेश ने कहा, 2014 से खासकर, इतिहास दो लोगों के समूह (जी2) और उनके तंत्र द्वारा बेधड़क विकृत और गलत पेश किया जा रहा है।

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, निस्वार्थ नेता उनके गलत इस्तेमाल से हैरान हो जाते, क्योंकि इस विचारधारा स्वतंत्रता संग्राम या संविधान निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाई और पटेल के शब्दों में, इसने ऐसा माहौल बनाया जो 30 जनवरी 1948 की खौफनाक त्रासदी को संभव बना सका। 1875 में गुजरात के नाडियाड में जन्मे पटेल स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। अपनी असाधारण नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र के एकीकरण के प्रति अडिग प्रतिबद्धता के लिए उन्हें भारत का लौहपुरुष के रूप में याद किया जाता है। उनका निधन 1950 में हुआ।

दिल्ली दंगा केसः राजधानी में था ही नहीं, कोई कॉल नहीं किया.. सुप्रीम कोर्ट में उमर, शरजील की क्या दलीलें

नई दिल्ली।

2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शरजील ईमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, गुल्फिशा फातिमा, शिफा उर रहमान और मुहम्मद सलीम खान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. आरोपियों की ओर से पेश हुए वकील अपनी-अपनी दलील रख रहे हैं सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम 11 अप्रैल 2020 से यानी पांच साल पांच महीने से जेल में बंद हैं. चार्जशीट बहुत पुरानी हो गई हैं. कई पूरक चार्जशीट दाखिल की गई हैं.

पहली चार्जशीट 2020 में और आखिरी पूरक चार्जशीट जून 2023 में दाखिल की गई. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजिरिया की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है. सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक एम. सिंघवी याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए हैं. उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा गुरुवार देर शाम जवाब दाखिल किया गया था. इसलिए अदालत ने

याचिकाकर्ता वकीलों को जवाब पढ़ने का समय दिया. मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी. सिब्बल ने दलील दी कि खालिद ने 17 फरवरी को अमरावती में भाषण दिया था और इसी आधार पर पुलिस ने आरोप लगाया कि उमर खालिद इस सब के लिए ज़िम्मेदार है! उसने हिंसा के बारे में कुछ नहीं कहा और यह एक सार्वजनिक भाषण है, जिसमें गांधीवादी सिद्धांतों की बात की गई है. तीन आरोपियों, जिनमें 2 महिलाएं और एक आसिफ इकबाल तन्हा, को हाई कोर्ट ने नियमित जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा. समानता के आधार पर इस पर भी फैसला किया जा सकता है. उमर खालिद के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब दिल्ली मे दंगे हुए उस समय उमर खालिद दिल्ली में नहीं था. उमर खालिद के खिलाफ आरोप साजिश का है. 751 एफ़आईआर हैं, उमर खालिद पर एक में आरोप है कि उसने दंगों की साजिश रची थी. लेकिन जिन तारीखों को दंगे हुए, उन तारीखों को उमर खालिद दिल्ली में नहीं था और न ही कोई पैसा, कोई हथियार बरामद हुए और न ही हिंसा से जुड़े कोई साक्ष्य मिले. किसी गवाह का बयान भी नहीं मिला, जो उमर खालिद को वास्तव में किसी हिंसा से जोड़ता हो. वे कहते हैं कि मैं ही समय ले रहा हूं और मामले में देरी कर रहा हूं, जबकि तथ्य कुछ और ही कहते हैं. मेरे खिलाफ साजिश का आरोप है. 751 एफआईआर दर्ज हैं. याचिकाकर्ता दंगों के समय दिल्ली में था ही नहीं. अगर मैं वहां नहीं हूं, तो दंगों को इससे कैसे जोड़ा जा सकता है 751 में से मुझे केवल एक में पक्ष बनाया गया. बेल नियम है, जेल अपवाद.. सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत में ये दलील दी. उन्होंने कहा, ताहिर हुसैन से मिले पैसे से आतंकी गतिविधि होने का आरोप लगा. पैसा कितना था, कहां से आया... इसका कोई सबूत नहीं है. मुझे ताहिर हुसैन से जोड़ने के लिए कोई कड़ी, तो पुलिस को दिखानी होगी. गुलफिशा पिंजरा तोड़ की सदस्य नहीं है. लेकिन इसमें शामिल दो अन्य लोगों को ज़मानत मिल गई है. पुलिस को यह बताने में एक साल लग गया कि चार्जशीट की जांच पूरी हुई है या नहीं.

वो सो रहे हैं, आने दीजिये हम निपट लेंगे, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से फिर मांगा जवाब

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस अनुरोध को खारिज कर दिया कि आवारा कुत्तों के मामले में पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी रायों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को अदालत में वर्चुअल रूप से पेश होने की अनुमति दी जाए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने स्पष्ट किया कि मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। न्यायमूर्ति नाथ ने टिप्पणी की कि जब अदालत अनुपालन हलफनामे मांगती है, तो आदेशों की अनदेखी की जाती है, इसलिए अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। मेहता ने पीठ से आभासी उपस्थिति की अनुमति देने का आग्रह किया, लेकिन अदालत ने इस अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिवों को पेश होने का आदेश दिया 27 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी रायों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को उसके समक्ष उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया था कि 22 अगस्त को अदालत के निर्देशों के बावजूद अनुपालन हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया गया। अपने 22 अगस्त के आदेश में न्यायालय ने आवारा कुत्तों के मामले का दायरा दिल्ली-एनसीआर से आगे बढ़ाते हुए सभी रायों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने नगर निकायों को भी अनुपालन हलफनामे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था जिसमें पशु जन्म नियंत्रण नियमों के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध डॉग पाउण्ड, पशु चिकित्सकों, डॉग कैचर, और विशेष रूप से सुसज्जित वाहनों और पिंजरों का पूरा विवरण दिया गया हो। राष्ट्रीय राजधानी में विशेष रूप से बच्चों में आवारा कुत्तों के हमलों के कारण रेबीज फैलने की बढ़ती घटनाओं के बारे में मीडिया रिपोर्टों पर संज्ञान लेने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले की स्वतः सुनवाई की जा रही है।

सांसों में जहर : बच्चों के फेफड़ों में मिली प्रदूषण की काली परत, सीएसई की रिपोर्ट में कई अन्य खतरे भी उजागर

नई दिल्ली।

सुबह खेलते बच्चों की जगह मास्क पहने, खांसते, हांफते छोटे चेहरे दिखाई दें तो यह केवल मौसम का बदलना नहीं, बल्कि भविष्य का डर है। भारत में वायु प्रदूषण अब अदृश्य खतरा नहीं रहा। यह बच्चों के फेफड़ों में काले धब्बों के रूप में दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिक और डॉक्टर स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि धूम्रपान न करने वाले बच्चों के फेफड़ों तक में काला जमाव पाया जा रहा है, जो धीरे-धीरे सांसों को खत्म कर सकता है। देश की पूरी 1.4 अरब आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है, जिसमें पीएम 2.5 स्तर डब्ल्यूएचओ के मानकों से अधिक है। उत्तर भारत में रहने वाले लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा में 7.6 वर्ष तक की कमी का अनुमान है। लखनऊ जैसे शहरों में यह नुकसान 9.5 वर्ष तक पहुंच सकता है और यह भार सबसे यादा बच्चों पर पड़ रहा है। सीएसई की रिपोर्ट सांसों का आपातकाल बताती है कि देश की 63त्न आबादी राष्ट्रीय मानक 40 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से अधिक प्रदूषण झेल रही है। इंडो-गैंगेटिक क्षेत्र बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की करीब 40त्न आबादी औसतन 7.6 वर्ष की जीवन अवधि खो रही है। 1998 से 2023 के बीच भारत में पीएम 2.5 स्तर में 61.4त्न की वृद्धि हुई है। वैश्विक प्रदूषण वृद्धि में 44त्न योगदान अकेले भारत का है। लंदन की 9 वर्ष की बच्ची एला किस्सी डेब्राह की 2013 में अस्थमा से मौत हुई थी। 2020 में अदालत ने पहली बार आधिकारिक रूप से कहा कि उसकी मौत का कारण वायु प्रदूषण था। यह दुनिया का पहला मामला है जिसने प्रदूषण को मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण माना। भारत की पर्यावरण स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. कल्पना बालाकृष्णन कहती हैं, प्रमाण की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति का प्रमाण नहीं होती। विशेषज्ञों के अनुसार, अत्यधिक प्रदूषण वाले दिनों में बच्चों को घर के अंदर रखें। सुबह-शाम बाहर खेलने से बचाएं। इस समय प्रदूषण अधिक होता है। बच्चों को बाहरी गतिविधियों में मास्क एन-95 या समतुल्य पहनाएं। घर में एयर प्यूरीफायर का उपयोग संभव हो तो करें। पोषण पर ध्यान दें।विटामिन सी, ओमेगा थ्री और एंटीऑक्सीडेंट फेफड़ों की रक्षा में मदद करते हैं। स्कूलों में क्लीन एयर प्रोटोकॉल लागू हों। दिल्ली और केंद्रीय अस्पताल हर सर्दी में विशेष निगरानी, प्रदूषण-ओपीडी और आपात तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मानते हैं कि यह अब मौसमी संकट नहीं, साल भर का स्वास्थ्य आपातकाल बन चुका है। भारत का वायु संकट अब अदृश्य नहीं रहा। यह हर बच्चे के फेफड़ों में देखा जा सकता है। आज अगर हवा साफ करने पर युद्ध स्तर पर कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ी का बचपन धुंध में खो जाएगा।

दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी पर भी थाने में होगी ई-एफआईआर, अब अपराध पर लगेगा लगाम

नई दिल्ली। पिछले साल दिल्लीवासियों को 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के साइबर अपराधों की मार झेलनी पड़ी, जिसके बीच दिल्ली पुलिस ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में ई-एफआईआर दर्ज करने की सीमा 10 लाख रुपये से घटाकर 1 लाख रुपये कर दी है। इस कदम का उद्देश्य त्वरित निवारण और मजबूत डिजिटल पुलिसिंग सुनिश्चित करना है। एक अधिकारी ने गुरुवार को घोषणा की कि 1 नवंबर से, 1 लाख रुपये या उससे अधिक की ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार अब ई-एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। यह नई सुविधा, जो पहले केवल 10 लाख रुपये या उससे अधिक की धोखाधड़ी के मामलों पर ही लागू होती थी, अब कम राशि की धोखाधड़ी के शिकार लोगों के लिए राष्ट्रीय राजधानी के किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराना आसान बना देगी। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, जहाँ एकीकृत सहायता डेस्क के कर्मचारी उनकी शिकायत दर्ज करेंगे और यदि धोखाधड़ी की गई राशि 1 लाख रुपये से अधिक है, तो ई-एफआईआर दर्ज करेंगे। विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध शाखा) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया,पहले हमें 10 लाख रुपये या उससे अधिक की धोखाधड़ी की 70 से 80 शिकायतें हर महीने मिलती थीं। सीमा को घटाकर एक लाख रुपये करने के नए फैसले के साथ, हमें उम्मीद है कि ई-एफआईआर दर्ज कराने के लिए यह संख्या बढ़कर हर महीने 700-800 हो जाएगी। श्रीवास्तव ने बताया कि नई पहल के तहत, जिन शिकायतकर्ताओं ने एक लाख रुपये या उससे अधिक की राशि खो दी है, वे 1930 पर साइबर हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं। कॉल लेने वाला व्यक्ति पोर्टल पर शिकायत दर्ज करेगा, जो स्वतः ही ई-एफआईआर में बदल जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस को 1930 हेल्पलाइन पर प्रतिदिन साइबर धोखाधड़ी से संबंधित 3,000 से अधिक कॉल आती हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि पीड़ित अब पुलिस स्टेशन जाकर नए स्थापित एकीकृत हेल्प डेस्क कर्मचारियों की सहायता से ई-एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।- उन्होंने आगे कहा कि ई-एफआईआर को आगे की जाँच के लिए संबंधित साइबर पुलिस स्टेशन भेज दिया जाएगा। विशेष पुलिस आयुक्त ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर के अलावा, राष्ट्रीय राजधानी में हमारे कुल 225 पुलिस स्टेशन हैं जहाँ पीड़ित आकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे हमें साइबर संबंधी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए अतिरिक्त कार्यबल मिलता है।

एनडीए के घोषणापत्र में ज्यादा दम है महागठबंधन के? वादों की बारिश के बीच मतदाता को क्या भायेगा?

नीरज कुमार दुबे

बिहार विधानसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और महागठबंधन दोनों ने अपने-अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्रियों जीतन राम मांझी, चिराग पासवान तथा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी में एनडीए ने अपना विस्तृत घोषणापत्र प्रस्तुत किया। एनडीए के घोषणापत्र में एक करोड़ रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे में निवेश पर ज़ोर दिया गया है। घोषणापत्र में हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, औद्योगिक पार्क, महिला उद्यमिता मिशन, खेती के लिए एमएसपी की गारंटी, और सात नए एक्सप्रेसवे जैसी योजनाओं की घोषणा की गई है। इसके साथ ही गरीबों के लिए 50 लाख नए घर, 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन और बेहतर शिक्षा-स्वास्थ्य ढांचा का वादा किया गया है।

राज्य के घोषणा पत्र के प्रमुख प्रावधानों में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आर्थिक सहायता का भी उल्लेख है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) को सरकार 10 लाख रुपये की सहायता देगी और उनके हितों के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग गठित किया जाएगा। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र के लिए राज्य ने 'कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि' शुरू करने की घोषणा की है, जिसे केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से लागू किया जाएगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी दी जाएगी और कृषि अवसंरचना में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। घोषणापत्र में कहा गया है कि बाढ़ प्रभावित उत्तर बिहार को अगले पांच वर्षों में पूरी तरह इस समस्या से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। शहरी विकास के तहत चार और शहरों में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की घोषणा भी की गई है। राजधानी क्षेत्र में 'न्यू पटना' नामक एक हरित (ग्रीनफील्ड) परियोजना विकसित की जाएगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीतामढ़ी के पुनौरा धाम जानकी मंदिर को सीतापुरम के रूप में विकसित किया जाएगा। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि बिहार में विदेश उड़ानें शुरू की जाएंगी और कई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। साथ ही, राज्य में 10 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे और प्रत्येक जिले में फैक्टरी एवं विनिर्माण इकाइयां शुरू की जाएंगी। राज्य ने वादा किया है कि अगले पांच वर्षों में राज्य में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे औद्योगिक क्रांति की गारंटी सुनिश्चित होगी।

शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने केजी से पीजी तक निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा किया है। अनुसूचित जाति के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य ने गरीब और वंचित वर्गों के लिए 'पंचामृत गारंटी' की घोषणा की है, जिसके तहत मुफ्त राशन, पांच लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, 50 लाख पक्के मकान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। राज्य ने घोषणापत्र में कहा कि खेल के क्षेत्र में राज्य में 'बिहार स्पोर्ट्स सिटी' का निर्माण किया जाएगा ताकि युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं मिल सकें। संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। घोषणा पत्र के अनुसार, गिग वर्कर्स और ऑटो चालकों को वित्तीय सहायता और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भाजपा ने कहा, यह घोषणापत्र प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और नीतीश कुमार के भरोसे का प्रतीक है। दूसरी ओर, महागठबंधन ने अपने घोषणापत्र जिसे 'तेजस्वी प्रण' नाम दिया गया है, में हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सत्ता में आए तो 20 दिन में हर परिवार को एक नौकरी दी जाएगी। घोषणापत्र में 'जीविका दीदी' को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने और युवा, किसान व महिला सशक्तिकरण से जुड़ी 25 प्रमुख घोषणाएँ शामिल हैं। देखा जाये तो बिहार की राजनीति में घोषणापत्र अब केवल नीतिगत दस्तावेज नहीं रहे, बल्कि भावनात्मक प्रोपेगेंडा बन चुके हैं। इस बार दोनों खेमों ने वादों की ऐसी बारिश की है कि आम मतदाता के लिए असली और नकली बादल में फर्क करना मुश्किल हो गया है।

एनडीए का घोषणापत्र दिखने में व्यावहारिक और संरचनात्मक है— यह विकास, उद्योग और स्थिरता की बात करता है। वहीं महागठबंधन का घोषणापत्र भावनात्मक है— यह नौकरी, वेतन और सरकारी स्थायित्व जैसे सीधे वादे करके युवाओं के दिलों को छूने की कोशिश करता है। एनडीए ने इस बार 'गारंटी' को मुख्य शब्द बनाया है। मोदी की गारंटी और नीतीश का भरोसा, यह नारा सीधे जनता की याददाश्त में बैठाने की रणनीति है। घोषणापत्र का फोकस बुनियादी ढांचे पर है। जैसे- 7 एक्सप्रेसवे, 3,600 किमी नई रेल लाइनें, हर जिले में मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक पार्क का वादा किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार में उद्योग लगाने का माहौल तैयार है? बिजली, भूमि, कानून व्यवस्था और मानव संसाधन, ये चारों चुनौतियाँ अभी भी गंभीर हैं। देखा जाये तो एक करोड़ रोजगार का वादा तब तक महज नारा रहेगा जब तक बिहार में पूंजी निवेश आकर्षक नहीं बनता। हालांकि, एनडीए ने महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं— लखपति दीदी मिशन और महिला उद्यमिता योजना के ज़रिए ग्रामीण महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। नीतीश कुमार का पिछला रिकॉर्ड इस दिशा में अपेक्षाकृत मजबूत रहा है, इसलिए इस वर्ग में एनडीए का वादा विश्वसनीय दिखता है। वहीं तेजस्वी यादव ने घोषणापत्र को पूरी तरह युवाओं के लिए डिज़ाइन किया है। 20 दिन में नौकरी जैसा वादा तात्कालिक रूप से आकर्षक जरूर लगता है, लेकिन वित्तीय दृष्टि से यह असंभव है। बिहार के राजस्व संसाधन सीमित हैं; अगर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, तो यह न केवल आर्थिक रूप से अव्यावहारिक होगा बल्कि शासन व्यवस्था भी चरमरा जाएगी। पुरानी पेंशन योजना, ठेका कर्मियों का स्थायीकरण और 'जीविका दीदी' को सरकारी दर्जा देने जैसी घोषणाएँ वित्तीय बोझ को कई गुना बढ़ा सकती हैं।

महागठबंधन ने भावनात्मक राजनीति का सहारा लिया है, पर शासन के व्यावहारिक समीकरणों को नजरअंदाज किया है। अब सवाल उठता है कि जनता किसके घोषणापत्र से प्रभावित होगी? देखा जाये तो बिहार की जनता अब केवल वादों से नहीं, विश्वसनीयता से प्रभावित होती है। नीतीश कुमार की छवि एक अनुभवी प्रशासक की है, भले ही अब उनकी लोकप्रियता घट रही हो। मगर मोदी फैक्टर आज भी ग्रामीण और मध्यम वर्ग में भरोसे का प्रतीक है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव युवाओं में उम्मीद जगाते हैं, लेकिन जंगलराज की पुरानी यादें अभी भी वोटरों के दिमाग में ताज़ा हैं।

इसलिए, शहरी और मध्यम वर्ग के मतदाता संभवतः एनडीए के विकास और स्थिरता के वादे से आकर्षित होंगे, जबकि बेरोजगार युवा और निम्न वर्ग महागठबंधन की नौकरी और पेंशन की घोषणाओं की ओर झुक सकते हैं। बहरहाल, एनडीए का घोषणापत्र एक दीर्घकालिक दृष्टि प्रस्तुत करता है लेकिन उसकी सफलता क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। वहीं महागठबंधन का घोषणापत्र तत्काल राहत का सपना दिखाता है लेकिन उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। बिहार के मतदाता अब भावनाओं से अधिक परिणाम चाहते हैं। वह जान चुके हैं कि रोज़गार की राजनीति और विकास की राजनीति के बीच एक बहुत गहरा अंतर है। बिहार के लिए असली सवाल यह नहीं है कि कौन ज्यादा वादे करता है, बल्कि यह है कि कौन अपने वादों को निभा सकता है। और इस बार, जनता घोषणापत्र नहीं, विश्वसनीयता को वोट देगी।

सम्पादकीय...

भारत-चीन सीमा विवाद!

भारत-चीन सीमा विवाद एक अनसुलझा प्रश्न है? जिसे सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच एक उच्च स्तरीय वार्ता तन्त्र स्थापित है। 2005 से दोनों देशों के बीच में इस वार्ता तन्त्र की दो दर्जन से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। इस तन्त्र में भारत की ओर से इसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन की ओर से इसके विदेश विभाग के मन्त्री शामिल है। यह वार्ता तन्त्र भारत-चीन के बीच पक्की सीमा रेखा खींचने के काम में लगा हुआ है। जाहिर है कि यह कार्य आसान नहीं है क्योंकि चीन उस मैकमोहन रेखा को नहीं मानता जो 1914 में भारत-चीन व तिब्बत के बीच खींची गई थी। चीन ने 1914 में सीमा रेखा खींचने के लिए शिमला में आयोजित उस बैठक का बहिष्कार कर दिया था जिसमें भारत-चीन-तिब्बत के बीच रेखा निर्दिष्ट की गई थी। शिमला में1914 में ब्रिटिश विशेषज्ञ मिस्टर मैकमोहन ने तिब्बत को स्वतन्त्र देश मानते हुए वार्ता में इसके प्रतिनिधि को भी बुलाया था। जिस पर चीनी प्रतिनिधि ने इस वार्ता का बहिष्कार कर दिया था। तब से लेकर आज तक भारत-चीन सीमा का मामला लटका हुआ है। इस बीच पूरे क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन आ चुका है। 1949 में चीन स्वतन्त्र राष्ट्र बना जबकि 1947 में भारत अंग्रेजों की दासता से मुक्त हुआ। चीन ने पचास के दशक में ही तिब्बत को अपना हिस्सा मानने की घोषणा कर दी। भारत ने 2003 तक तिब्बत को स्वतन्त्र इकाई माना परन्तु इस वर्ष हुकूमत पर काबिज भाजपा नीत एनडीए सरकार के मुखिया स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने परम्परा से हट कर तिब्बत को चीन का स्वायत्तशासी प्रदेश स्वीकार किया और भारत-चीन सीमा विवाद सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता तन्त्र गठित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी। 2004 में केन्द्र में कांग्रेस नीत मनमोहन सरकार गठित हुई और इसने वाजपेयी सरकार द्वारा छोड़े गये कार्य को पूरा किया और दोनों देशों के बीच वार्ता तन्त्र स्थापित किया। भारत में सरकार एक सतत् प्रक्रिया होती है और हर अगली सरकार को पिछली सरकार द्वारा छोड़े गये कामों को पूरा करना पड़ता है। यह कार्य अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में विशेष तौर पर विदेश विभाग को करना पड़ता है। मनमोहन सरकार के बाद केन्द्र में बनी भाजपा नीत मोदी सरकार ने भी इस क्रम को आगे बढ़ाया और उच्च स्तरीय वार्ता तन्त्र की बैठकों को आयोजित किया। हालांकि दो दर्जन से अधिक बैठकों के आयोजित होने के बावजूद सीमा का सवाल बदस्तूर टिका हुआ है। मगर जून 2020 में चीन ने भारत के लद्दाख इलाके में जबर्दस्त अतिक्रमण किया जिसमें भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। हालांकि अच्छी खासी संख्या में चीनी फौजी जवान भी हलाक हुए। उसके बाद से सीमा का यह इलाका तनाव भरा माना जाने लगा। चीन जब भी भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे अवधारणा का मुद्दा बना देता है। तब से लेकर अब तक भारत व चीन के कोर कमांडरों के बीच वार्ता के 23 दौर हो चुके हैं। कोर कमांडरों की बैठक में वर्तमान में लद्दाख सीमा पर फौजी गश्त लगाने के साथ ही शान्ति व सौहार्द बनाये रखने के उपायों पर बातचीत की जाती है जिससे दोनों देशों के बीच जो नियन्त्रण रेखा है वह पूरी तरह शान्त रहे। फिलहाल सीमा के दोनों ओर दोनों देशों ने कम से कम अपने 50-50 हजार सैनिक तैनात कर रखे हैं। अतः लद्दाख सीमा पर फौजों की तैनाती को देखते हुए शान्ति बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यही वजह है कि कोर कमांडर आपस में बातचीत करते रहते हैं जिससे किसी भी सूरत में तनाव पैदा न हो। हाल ही में दोनों देशों के कमांडरों ने लद्दाख सीमा पर स्थित चुशूल-माल्दो इलाके में बातचीत की और यह अहद किया कि सरहदों पर शान्ति बनाये रखने के लिए दोनों देश कटिबद्ध हैं। यह वार्ता का 23 वां दौर था। इससे पूर्व पिछले वर्ष हुई कमांडरों की 22वीं बैठक में यह तय किया गया था कि दोनों ओर के फौजी आपस उलझेंगे नहीं और यथास्थिति बनाये रखेंगे। अतः लगभग एक वर्ष बाद फिर से कमांडरों ने शान्ति व सौहार्द बनाये रखने के प्रति अपनी रजामन्दी दिखाई है। भारत-चीन के बीच बनी वास्तविक नियन्त्रण रेखा का सम्मान करने से ही दोनों देशों के बीच मित्रता बनी रह सकती है। जैसा कि सभी को मालूम है कि चीन की सोच सैनिक सोच (मिलिट्री माइंडेड) है अतः उसे सीमा पर सैनिक कार्रवाइयों से रोकना छोटी बात नहीं है क्योंकि चीन जब भी भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण करता है तो कह देता है कि यह उसकी अवधारणा की वजह से हुआ है। निश्चित रूप से चीन का शुमार विश्व शक्तियों में होता है मगर इसका मतलब यह नहीं है कि वह सीमा के आसपास के इलाकों पर अपना दावा ठोकता रहे परन्तु पिछले वर्ष चीन इस बात पर राजी हो गया था कि लद्दाख सीमा पर वह पूरी तरह शान्ति बनाये रखेगा। अतः विगत 25 अक्तूबर को हुई 23वीं दौर की कमांडर बैठक में यही अहद किया गया है। दोनों देशों के सैनिक कमांडरों की बैठक जब शान्ति व सौहार्द की बात करती है तो इसका अर्थ सीधे-सीधे यही निकलता है कि जो उच्चस्तरीय वार्ता तन्त्र है वह अपना काम आगे बढ़ाये और सीमा विवाद को हल करने के प्रयास तेज करे। क्योंकि चीन ऐसा देश है जिसके साथ छह ओर से भारत की सीमाएं लगती है। साथ ही चीन भारत का ऐसा पड़ोसी देश है जिसने 1962 में अकारण ही भारत पर हमला कर दिया था और अपनी फौजें असम के शहर तेजपुर तक पहुंचा दी थीं। इसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय दबाव बनने पर चीन ने अपनी फौजों की वापसी की थी और वे मनमाने ढंग से सीमा पर आ गई थीं परन्तु यह 2025 चल रहा है और इस दौरान वैश्विक वास्तविकताएं आमूल-चूल रूप से बदल चुकी हैं। चीन के मामले में भारत का रुख सकारात्मक हो रहा है परन्तु चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से यदा-कदा भारत को उकसाता रहता है। जबकि नब्बे के दशक में केन्द्र में पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार के रहते कई आपसी समझौते हुए थे जिनमें सीमा पर शान्तिपूर्ण प्रबन्धन मुख्य था।

चलता-फिरता मौत का सफर, द बर्निंग बस

भारत में स्लीपर बसें लंबे समय से आरामदायक सफर का प्रतीक मानी जाती रही है। रात में सोते-सोते मंजिल तक पहुंच जाने का सपना-लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। देश में बीते दो सप्ताह में तीन बड़े बस हादसे में करीब 50 यात्रियों की जल जाने से मौत हो गई। इसमें भी अधिकांश यात्री सफर के दौरान नींद में थे। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही 46 यात्रियों वाली एक लग्जरी बस की दुर्घटना ऐसी ही पिछली त्रासदियों की तरह थी। यह दुर्घटना स्पष्ट रूप से ईंधन रिसाव के कारण हुई थी, जब बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी थी, जो पहले एक हिट-एंड-रन घटना में जमीन पर गिर गई थी। इस दुर्घटना में बाइक सवार सहित 20 लोगों की जान चली गई। बचे लोग बमुश्किल टूटी खिड़कियों से बच पाए। लगभग 10 दिन पहले, जैसलमेर से जोधपुर जा रही 57 यात्रियों वाली एक वातानुकूलित बस में आग लगने से 20 लोग जिंदा जल गए थे। वहीं मध्य प्रदेश के अशोक नगर में रात सवारियों को लेकर इंदौर जा रही एक स्लीपर बस में आग लग गई, हालांकि सभी यात्री बच गए। इतना ही नहीं कुछ बड़े देश स्लीपर बसों को अपने यहां बैन कर चुके हैं, वे बसें भारत में लग्जरी सफर की पहचान बन गई है लेकिन एक बार बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर क्या स्लीपर बस सुरक्षित हैं या नहीं। जर्मनी में कई बड़ी दुर्घटनाओं की वजह से 2006 में स्लीपर बसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बताया जाता है कि 2000 के दशक में जर्मनी में यह बसें काफी लोकप्रिय हो गई थीं। इन बसों की ऊंची बनावट के कारण इनके पलटने का खतरा भी अधिक था। साथ ही सोते समय यात्रियों के बेल्ट नहीं बांधने से हादसा होने पर उछलकर गिरने से उनकी मौत हो जाती थी। चीन ने 2012 में कई भीषण आग और सड़क हादसों के बाद 2012 में जाकर नई स्लीपर बसों के निर्माण और रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था और 2018 में सभी पुरानी स्लीपर बसें हटा दीं। चीन में रेल नेटवर्क की कमी के कारण 1990 के दशक के दौरान स्लीपर बसों की शुरूआत हुई। चीन में 2009 से 2012 के दौरान 13 हादसों में 252 लोगों की मौत ने हिलाकर रख दिया। इसके बाद गाइडलाइन कड़ी की गईं लेकिन उसका लाभ नहीं मिला। फलस्वरूप डिजाइन की कमी, लंबे सफर में ड्राइवर को आराम न मिलने, ओवरलोडिंग और सीटों के बीच कम जगह के कारण इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। वियतनाम में सुरक्षा कारणों से स्लीपर बसों पर प्रतिबंध लगाया है। इंग्लैंड में सुरक्षा मानकों और आपातकालीन निकासी की चुनौतियों के कारण इन पर प्रतिबंध है। भारत हर हादसे के बाद पोस्टमॉर्टम करता है-रोकथाम नहीं। सिस्टम की - 78फीसदी बसें प्राइवेट हाथों में है। भारत में करीब 16 लाख बसें चलती हैं, जिनमें से 78फीसदी छोटे प्राइवेट ऑपरेटर चलाते हैं, कई के पास पांच से भी कम बसें है। ऐसे में सुरक्षा की मॉनिटरिंग लगभग असंभव है। कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बढ़ते मुनाफाखोर ऑपरेटरों ने हालात को और खतरनाक बना दिया है। यात्रियों की जान दांव पर लगाकर अवैध वायरिंग, ओवरलोडिंग और बिना सर्टिफिकेशन वाली बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। आमतौर पर इनमें से ज्यादातर बसों पर जाने-माने ब्रांड के नाम होते हैं लेकिन सच्चाई यह है कि इन ओईएम से केवल ईंजन और चेसिस ही खरीदे जाते हैं। फिर चेसिस को बॉडी-बिल्डिंग की दुकानों में एक पूरी बस में बदल दिया जाता है। हालांकि, अक्सर उन्नत होते इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और एयर-कंडीशनिंग सिस्टम में बिजली से आग लगने का खतरा होता है, फिर भी इन प्रणालियों को डिजाइन और इंस्टॉल करते समय आमतौर पर कड़े सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है लेकिन बॉडी की स्थापना और बॉडी शॉप में किए गए संशोधनों में जो सख्ती नहीं बरती जाती, वह है। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा विकसित ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस) बॉडी के लिए संरचनात्मक और अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं को भी निर्धारित करते है लेकिन इनका पालन शायद ही कभी किया जाता है। अक्सर, बॉडी घटिया गुणवत्ता वाली मिश्रित सामग्री से बनी होती है जो अत्यधिक ज्वलनशील होती है। क्रैश टेस्टिंग शायद ही कभी होती है। बॉडी शॉप में कभी-कभी अतिरिक्त ईंधन टैंक लगाने जैसे असुरक्षित संशोधन किए जाते हैं। बस में स्लीपर की व्यवस्था यात्रियों की आवाजाही को बाधित करती है। पर्दे और अन्य बैकिट्स के लिए नरम, अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग किया जाता है। हाल के नियमों में निर्दिष्ट किया गया है कि ऐसी बसों में चार निकास होने चाहिए (दो मुख्य द्वार और दो सिमटने वाली खिड़कियां) जिनमें कोई सीट या स्लीपर बाधा न बने लेकिन ये मौजूदा बसों के बेड़े पर लागू नहीं होते। ड्राइवरों को अक्सर आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। यह अनिवार्य करने से सुरक्षा बढ़ेगी कि आपातकालीन निकास व्यवस्था यात्रियों को समझा दी जाए क्योंकि वे उड़ान में हैं। टक्करों के दौरान सुरक्षा बढ़ाने के लिए पूरी बस असेंबली का क्रैश परीक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए। हालांकि वर्तमान मानक अग्नि पहचान और सुरक्षा प्रणालियों को अनिवार्य करते हैं जो आग लगने पर चेतावनियां देंगी और उसके बाद अग्निशमन उपकरणों को सक्रिय करेंगी, इनका बॉडी शॉप में शायद ही कभी पालन किया जाता है। जरूरत एक अधिक व्यापक एआईएस की है जो स्लीपर बसों में जोखिमों को ध्यान में रखे अगर चीन और वियतनाम जैसे देश ऐसे डिजाइन को बैन कर सकते है तो भारत क्यों नहीं? जरूरत है कि अब इस पूरे सिस्टम को झकझोरा जाए। केवल हादसों पर दुख जताने या जांच बिठाने से काम नहीं

प्रौद्योगिकी में भारत की राह पर दुनिया

भारत आज वैश्विक वैज्ञानिक पुनर्जागरण के द्वार पर खड़ा है। तकनीक से समृद्ध भारत आज केवल अनुयायी नहीं है, बल्कि दूसरों को भी उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर रहा है। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखी है। डिजिटल सशक्तिकरण से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक, आत्मनिर्भर और तकनीक-प्रधान भारत की रूपरेखा अब स्पष्ट दिख रही है। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलताओं से लेकर स्वच्छ भारत और वन हेल्थ जैसे अभियानों तक देश ने यह साबित किया है कि विज्ञान, तकनीक और नवाचार के माध्यम से बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाया जा सकता है। यूपीआई क्रांति ने डिजिटल भुगतान की परिभाषा ही बदल दी है और भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बना दिया है। भारत की जैव-अर्थव्यवस्था ने पिछले दस वर्षों में जबरदस्त प्रगति की है। 2014 में जहां इसका मूल्य 10 अरब डॉलर था, वहीं 2024 में यह बढ़कर लगभग 165.7 अरब डॉलर हो गया है। भारत अब बायोफ्यूल, बायोप्लास्टिक और ग्रीन केमिकल्स जैसे क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। चंद्रयान और गगनयान मिशनों ने भारत की पहचान अंतरिक्ष शक्ति संपन्न देशों में मजबूत की है, जबकि 5जी नेटवर्क की शुरुआत और डिजिटल कूटनीति ने देश के दूर-दराज इलाकों तक कनेक्टिविटी और सशक्तिकरण पहुंचाया है। भारत अब सबके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बुद्धिमत्ता और नवाचार का लाभ हर क्षेत्र तक पहुंचे। चाहे वह कृषि हो, स्वास्थ्य सेवा हो या शासन व्यवस्था। देश में 100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां और युवाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स का मजबूत नेटवर्क भारत की वैज्ञानिक और उद्यमशीलता की भावना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन, क्वांटम विज्ञान और तकनीक, सेमीकंडक्टर निर्माण और सटीक कृषि जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति यह दिखाती है कि भारत अब केवल दुनिया के साथ कदम नहीं मिला रहा, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने में मदद कर रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत की कहानी है। एक ऐसा आत्मविश्वासी और दूरदर्शी भारत जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर, अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक, दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। ईएसटीआईसी - उपलब्धि से आकांक्षा तक इस प्रगति की पृष्ठभूमि में 3 से 5 नवंबर 2025 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में होने वाला इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव एक साहसिक नया कदम है। भारत सरकार के 13 मंत्रालयों की ओर से आयोजित यह सम्मेलन सिर्फ उपलब्धियों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह सहयोग, दूरदृष्टि और राष्ट्रीय रणनीति का मंच है। माननीय प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन किए जाने वाला ईएसटीआईसी 2025 देश-विदेश के प्रमुख वैज्ञानिकों, नवाचारकर्ताओं, नीति-निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा ताकि वे नई उभरती तकनीकों के भविष्य पर विचार-विमर्श कर सकें। यह सम्मेलन एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करेगा जहां कमियों की पहचान, साझेदारियां स्थापित करना और विज्ञान व प्रौद्योगिकी को भारत की विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप दिशा देना- इन सभी पर संयुक्त रूप से काम किया जाएगा।

पत्नियां सावधान रहें ?- हाईकोर्ट का फैसला - बुजुर्ग सास-ससुर के साथ दुर्व्यवहार,झगड़ा- विवाद या उपेक्षा करना मानसिक क्रूरता माना जाएगा, जो तलाक का आधार बन सकता है

वैश्विक स्तरपर भारत आदि अनादि काल से संयुक्त परिवारों में बसा-बसा रहा है, जबकि विदेशों में यह प्रथा बहुत कम देखने को मिलती है? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सामाजिक- आर्थिक कारणों तक सीमित नहीं है,बल्कि इसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा वैधानिक घटक सम्मिलित है।भारत में पारंपरिक रूप से कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था रही है, जहाँ जमीन-सम्पत्ति, श्रम, उपजी तथा आय परिवार-स्तर पर साझा होती थी। एक बड़े घर-परिवार (पिता-दादा-सास-ससुर-भाई-बहन-पति -पत्नी-बच्चे) से संसाधन-वितरण, काम-वितरण और सुरक्षा-नेटवर्क (जोड़-तोड़ व आर्थिक संकट में सहायता) अधिक सुगम होता था। इसके परिणामस्वरूप, 'संयुक्त परिवार' सामाजिक रूप से गढ़ा गया। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि इसके अतिरिक्त, हिन्दू परम्पराओं में पिता-दादा का पारिवारिक प्रधान होना वंश- परम्परा की निरंतरता, संपत्ति- विरासत का साझा स्वभाव, तथा वृद्धों- का परिवार में सम्मान व देखभाल का सामाजिक मान-दंड रहा है। इसके विपरीत अनेक पश्चिमी देशों में ऐसे में संयुक्त परिवार-प्रथा बहुत कम विकसित हुई। लेकिन यह प्रथा आज भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, आधुनिक जीवनशैली, आर्थिक-स्वतंत्रता, शहरीकरण, अलग रहने की प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपेक्षाएं बदल रही हैं। इसलिए, आज 'संयुक्त परिवार' का आधार कमजोर होते हुए दिख रहा है, और इस परिवर्तन-प्रक्रिया का प्रभाव विवाह-परिवार-वृद्ध देखभाल संबंधी कानूनी नियामक आयामों पर भी पड़ रहा है। आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है कि, हिन्दू मैरिज एक्ट,1955 की धारा 13(1)(ia) में ऐसा व्यवहार कि पति या पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य स्वाभिमान या अस्तित्व पर ऐसा प्रभाव पड़ता हो कि विवाह चलना असंभव या अस्वीकार्य हो जाए जैसे गुण- दोष है। इस प्रकार में, यदि पत्नी अपने सास-ससुर की देखभाल नहीं करती, उनके प्रति उपेक्षित व्यवहार करती है, उनकी स्वास्थ्य - स्थिति की जानकारी में उदासीनता, उत्तरदायित्व की अनदेखी ,विवाद उत्पन्न करती है, या अपमानजनक तथा निंदनीय भाषा-व्यवहार करती है,तो यह मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आता है। यानें अब बुजुर्ग सास-ससुर के साथ दुर्व्यवहार, झगड़ा-विवाद या उपेक्षा करना मानसिक क्रूरता माना जाता है, जो तलाक का आधार बन सकता है। यह प्रत्यक्ष रूप से उन नीतियों-विधियों एवं कानूनों से जुड़ा है जो विवाह-संबंधों में मानसिक क्रूरता (मेन्टल क्रूएल्टी) को एक मान्य तलाक- कारण के रूप में स्वीकार करते है। साथियों बात अगर हम दिल्ली हाई कोर्ट के केस नंबर एमएटी एपीपी 8/2022 पर दिनांक 19 सितंबर 2025 को माननीय दो जजों की बेंच ने 28 पृष्ठों में दिए जजमेंट की करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने पारिवारिक अदालत के उस आदेश के खिलाफ पत्नी की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें क्रूरता के आधार पर पति को तलाक दिया गया था। पति- पत्नी की शादी मार्च 1990 में हुई थी और 1997 में उनका एक बेटा हुआ। पति के आरोप है कि बीवी संयुक्त परिवार में रहने को तैयार नहीं थी। बिना अनुमति के अक्सर वैवाहिक घर छोड़ देती थी और 2008 से वैवाहिक संबंधों से दूर हो गई थी। यही नहीं,पति और उसके परिवार पर संपत्ति अपने नाम ट्रांसफर करने का दबाव डालती थी।जब पति ने 2009 में तलाक मांगा,तो पत्नी ने उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज करा दिए। पारिवारिक अदालत ने तलाक इस आधार पर दिया था कि पत्नी का लंबे समय तक साथ रहने से इनकार करना और बदले की भावना से झूठी शिकायतें (एफआईआर) दर्ज कराना मानसिक क्रूरता है। अपील में पत्नी का तर्क था कि निचली अदालत ने उन सबूतों पर भरोसा किया जो कागजात में नहीं थे और दहेज उत्पीड़न तथा दुर्व्यवहार के उसके आरोपों को नजरअंदाज किया।उसने दावा किया कि उसकी आपराधिक शिकायतें सच्ची थीं,बदले की भावना से नहीं की गई थीं। दिल्ली हाई कोर्ट को पत्नी के दावों में कोई दम नहीं लगा। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि लंबे समय तक वैवाहिक संबंध से इनकार और सास ससुर और पति को बार-बार परेशान करने वाले काम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत मानसिक क्रूरता है।यदि पत्नी पति तथा सास-ससुर के बीच झगड़ा करती है, उनके- उनके प्रति ध्यान नहीं देती, उपेक्षा करती है,अपमानजनक या निंदनीय आरोप लगाती है, मार-पीट करती है या अपमान जनक भाषा का प्रयोग करती है,तो वह व्यवहार मानसिक क्रूरता माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि संपूर्ण हिन्दू संयुक्त परिवार में माता-पिता एक अभिन्न अंग होते हैं, तथा जीवनसाथी द्वारा उनके प्रति उदासीनता या बेरुखी दिखाना विवाह-विवाद के संदर्भ में 'क्रूरता' के दायरे को और बढ़ा देता है। साथियों बात अगर हम इस महत्वपूर्ण जजमेंट के सामाजिक - वैधानिक विश्लेषण को समझने को करें तो,इस निर्णय का दोनों- आयामों में महत्व है। पहले सामाजिक पक्ष- भारत में जहां संयुक्त- परिवार-प्रथा आम है, वहाँ वृद्धों की देखभाल और परिवार- सदस्यों द्वारा उनका सम्मान व उत्तरदायित्व निभाना अपेक्षित रहा है।यदि जीवनसाथी इस दायित्व को स्वीकार नहीं करता, तो एक सामाजिक- नैतिकअपेक्षा टल जाती है और पारिवारिक संतुलन बिगड़ता है। साथ ही, जब सास-ससुर जैसी वृद्ध- पदस्थ व्यक्तियों के प्रति उदासीनता हो,तो यह सिर्फ घरेलू अनुकूलता का प्रश्न नहीं बल्कि पारिवारिक संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वृद्ध माता-पिता परिवार के अभिन्न अंग है, केवल सह-निवासी नहीं।इस तरह इस निर्णय ने एक तरह से यह संदेश दिया है कि विवाह सिर्फ पति-पत्नी का संबंध नहीं है, बल्कि उस संबंध में (विशेषकर हिन्दू-परिप्रेक्ष्य में) ससुराल-परिवार, माता-पिता, संयुक्त-परिवार-सदस्यों के प्रति जिम्मेदारियाँ भी सम्मिलित हैं। यदि जीवनसाथी उन जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रहे,तो उस व्यवहार को कानूनी रूप से क्रूरता माना जा सकता है। साथियों बात अगर हम इस जजमेंट को अन्तर्राष्ट्रीयदृष्टिकोण से देखें, तो विवाह-दोस्त- परिवार -संरचना-के संबंध में पश्चिमी देशों और भारत के बीच अंतर पाया जाता है।जैसे कि संयुक्त- परिवार-प्रथा पश्चिमी देशों में इतनी प्रचलित नहीं है,इसलिए वहाँ सास-ससुर देखभाल या संयुक्त-वृद्ध-पदस्थ सदस्य- सदस्यता जैसी अपेक्षाएँ इतनी ज़ोर से सामाजिक रूप से नहीं पाई जातीं। परिणामस्वरूप, वहाँ विवाह-क्रूरता के मामलों में प्रमुखतः अपेक्षित-देखभाल -उपेक्षा- वृद्ध-सदस्यों-की उपेक्षा जैसे तर्क कम-मिलते है। भारत में इस तरह की सामाजिक- पारिवारिक संरचना रहने के कारण, उपरोक्त निर्णय में वृद्ध-ससुराल-देखभाल-उपेक्षा-का आयाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।इस दृष्टि से,भारत-जैसी संरचनाओं वाले समाजों में इस तरह का कानूनी निर्णय विशेष प्रेरणा देता है,कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को सिर्फ सामाजिक -मानदंड नहीं, बल्कि कानूनी-अनिवार्यता के रूप में देखा जा सकता है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि, भारत में 'संयुक्त-परिवार' का गढ़ना उस सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का परिणाम है जहाँ वृद्ध-सदस्यों के कार्य, वस्तु व सम्मान-संबंधी पारिवारिक दायित्वों का सांस्कृतिक आधार रहा है।आज जब आधुनिक जीवनशैली -शहरीकरण-स्वतंत्रता जैसी प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं, तो इन पारंपरिक संरचनाओं में तनाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसे समय में दिल्ली हाई कोर्ट का ताज़ा निर्णय,जिसमें सास-ससुर के प्रति उपेक्षा-उदासीनता को 'मानसिक क्रूरता'मानकर तलाक-का आधार बताया जानासामाजिक -वैधानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।यह निर्णय जीवन साथियों तथा परिवार- सदस्यों को स्पष्ट संदेश देता है कि वृद्ध-सदस्यों-के-प्रति व्यवहार -उपेक्षा-संवेदनहीनता सिर्फ नैतिक दृष्टि से नहीं,बल्कि कानूनी दृष्टि से भी विवाह संबंध को प्रभावित कर सकती है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वरुण ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैंचशील एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/00862)

कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि व सरदार पटेल की मनाई जयंती

फतेहपुर।

आज कांग्रेस कार्यालय ज्वालागंज में कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के साथ साथ सरदार वल्लभभाई पटेल एवं आचार्य नरेंद्र देव की जयंती का भी आयोजन किया। आयोजन में सभी कांग्रेसियों ने स्व. इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी शहादत को याद करते हुए सरदार पटेल व आचार्य नरेंद्र देव के जीवन चरित्र पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष महेश द्विवेदी ने कहा कि इंदिरा जी का साहस और बलिदान दोनों हमें देश प्रेम की शिक्षा देते हैं उनका आदर्श असल जीवन मूल्यों का दर्शन है जो हमें एक सम्मानित जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। इसी के साथ सरदार पटेल जी व आचार्य नरेंद्र देव के राष्ट्रप्रेम एवं उनके द्वारा राष्ट्र निर्माण की भूरी भूरी प्रशंसा की। शहर अध्यक्ष आरिफ गुड्डा ने भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को एक कुशल रणनीतिकार एवं कुशाग्र चिंतक करार देते हुए कहा कि हम उनके बनाए मार्ग पर चलते रहें उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार सरदार पटेल जी ने निस्वार्थ एक मजबूत भारत की नींव रखी उससे भी हमे प्रेरणा की आवश्यकता है साथ ही आचार्य नरेंद्र देव जी की भी देश के लिए त्याग और तपस्या का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। कार्यक्रम में तमाम वरिष्ठ जनों के साथ राम नरेश महराज, माधुरी रावत, शोभा दुबे, शकीला बानो, मिस्बाहुल हक,अजय बच्चा, कौशल कुमार शुक्ला, नजमी कमर, ऋषभ पांडेय, अब्दुल रज्जाक, वकील खान, मो. अकरम काले, नसीम अंसारी, रमजान शाह, मोहित मिश्रा, असलम, आरिफ खान, पप्पू पाल, चंद्र प्रकाश लोधी बसीर अहमद, डॉ. अब्दुल हमीद, नसीम अंसारी , निजामुद्दीन आदि लोग उपस्थित रहे।

श्रीमदभागवत कथा के श्रवण से सुखमय होता जीवन-आचार्य धरणीधर

अयोध्या।

बेरासपुर कुडी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर अयोध्या से आए कथा प्रवक्ता आचार्य धरणीधर जी महाराज ने कहा हम भाग्यशाली है कि हमने सनातन धर्म में जन्म लिया है। असली पोषण भगवान की भक्ति से होता है। व्यक्ति उचित भोजन, व्यायाम करे वह व्यक्ति स्वस्थ, हष्ठ-पुष्ट होता है। उसी प्रकार भगवान की चर्चा करो भगवान का कीर्तन करो, भगवान का दर्शन करो, संतो का दर्शन करो, जितनी परिक्रमा करो, जितना तीर्थ दर्शन करो यह सब मोक्ष के मार्ग हैं। आचार्य धरणीधर जी महाराज ने कहा कि परमात्मा ही परम सत्य है। जब हमारी वृत्ति परमात्मा में लगेगी तो संसार गायब हो जाएगा। प्रश्न यह है कि परमात्मा संसार में घुले-मिले हैं तो संसार का नाश होने पर भी परमात्मा का नाश क्यों नहीं होता। इसका उत्तर यही है कि भगवान संसार से जुड़े भी हैं और अलग भी हैं। आकाश में बादल रहता है। और बादल के अंदर भी आकाश तत्व है। बादल के गायब होने पर भी आकाश गायब नहीं होता। इसी तरह संसार गायब होने पर भी परमात्मा गायब नहीं होते। संसार की कोई भी वस्तु

व्यक्ति उचित भोजन, व्यायाम करे वह व्यक्ति स्वस्थ, हष्ट-पुष्ट होता है। उसी प्रकार भगवान की चर्चा करो भगवान का कीर्तन करो, भगवान का दर्शन करो, संतो का दर्शन करो, जितनी परिक्रमा करो, जितना तीर्थ दर्शन करो यह सब मोक्ष के मार्ग हैं।

भगवान से अलग नहीं है उन्होंने कहा कि सत्संग में वह शक्ति है, जो व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों को अपने जीवन में क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, संग्रह आदि का त्याग कर विवेक के साथ श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए जब जब पृथ्वी पर अत्यचार बढ़ता है भगवान अवतार लेकर आते हैं सभी भक्तों ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया इस अवसर पर छट्ठू पाण्डेय, आचार्य सच्चिदानंद मिश्र,वृजकिशोर पाण्डेय, राजेश पाण्डेय, रंजीत पाण्डेय, नन्द किशोर पाण्डेय, राम जी पाण्डेय, रजनीश पाण्डेय, राजन पाण्डेय, कामता प्रसाद पाण्डेय, ओमप्रकाश पाण्डेय,विजय शंकर पाण्डेय समेत तमाम लोग मौजूद रहे।

आचार्य नरेन्द्र और सरदार पटेल को सपाईयों ने किया नमन

मुरादाबाद। समाजवादी पार्टी के महानगर कैंप कार्यालय पर आचार्य नरेंद्र देव जी और सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष इकबाल अंसारी ने की और संचालन दाऊद अंसारी ने किया। वक्ताओं के तौर पर सलीम वारसी, फहीम मंसूरी, अहमद मुरादाबादी, हाजी राशिद हुसैन अंसारी, जियाउल करीम अंसारी, मोनिस अली, मोहम्मद अजीम अध्यक्ष वार्ड 52, शादाब अली, मोहम्मद मुशर्रफ, मोहम्मद आरिफ, हसीन बेग, शब्बू, रियासत हुसैन, मसरूर हसन, मोहम्मद सुबहान, मोहम्मद आमान, लईक अहमद , अरबाज, शमशाद अंसारी, सरफराज, अशफाक अंसारी, शमशाद हुसैन, लालू परवेज आदि मौजूद रहे। वक्ताओं ने दोनों शख्सियतों की जिंदगी पर रोशनी डाली। महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी ने कहा कि इन महापुरुषों की कुर्बानियां रहीं कि हम आज आजाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। हर हिंदुस्तानी को चाहिए उनकी जिंदगी से प्रेरणा लेकर हिंदुस्तान को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का इरादा करें।

मेरा युवा-भारत खेत तत्वावधान में निकली राष्ट्रीय पदयात्रा

मुरादाबाद।

मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वधान में भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य पदयात्रा का आयोजन किया गया।

सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के लौहपुरुष आधुनिक भारत के निर्माताओं में एक है। उन्होंने पांच सौ से अधिक रजवाड़ों को जोड़कर विशाल भारत की नींव रखी उनके योगदान को वर्तमान पीढ़ी से परिचित कराने के उद्देश्य से यह पदयात्रा आयोजित की गई पदयात्रा का शुभारंभ अंबेडकर पार्क सिविल लाइन से किया गया एवं पदयात्रा अपने पहले पड़ाव में पीली कोठी के चौराह पर पहुँची जहाँ सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि की गई सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती की पदयात्रा के इस पहले पड़ाव पर जनप्रतिनिधि माननीय विधायक रामवीर सिंह, रीतेश गुप्ता ,जपाल सिंह व्यस्त ,सतपाल सिंह सैनी ने पदयात्रा की अगवानी की एवं इसके बाद पदयात्रा जिलाधिकारी निवास पर अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंची जहां जिलाधिकारी अनुज सिंह एवं मंडलायुक्त अंजनेन सिंह ने पदयात्रा की अगवानी की जबकि मधुबनी चौराहे पर जनपद के पुलिस कप्तान ने पदयात्रा के तीसरे पड़ाव पर अगवानी की एवं पदयात्रा सोनपुर स्टेडियम में आकर संपन्न हुई और पदयात्रा के अंतिम पड़ाव पर मुख्य विकास अधिकारी मृणाल जोशी ने अगुवानी की पदयात्रा का सम्पूर्ण आयोजन उप निदेशक अंकित कुमार गौर के नेतृत्व में मेरा युवा भारत में केंद्र सरकार नवगठित विभाग की मुरादाबाद इकाई ने किया है इस पदयात्रा के बारे में अंकित कुमार गौर ने बताया कि पदयात्रा में कुल ×000 युवाओं ने प्रतिभाग किया। इस पद यात्रा को शिक्षा विभाग क्रीड़ा विभाग युवा कल्याण नगर निगम यातायात विभाग के समन्वय से आयोजित करवाया गया इस सफल पदयात्रा में जिला क्रीड़ाधिकारी सुनील कुमार भगवानदास के साथ-साथ जनपद मुरादाबाद के प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक डॉज दीपक में धीरता के संस्थान का विशेष सहयोग रहा। इस पदयात्रा में युवाओं की के लिए पुलिस सुरक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यात्रा में शामिल हुई ।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर कलेक्ट्रेट में हुआ कार्यक्रम

मुरादाबाद। स्वतंत्र भारत के वास्तुकार लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती (राष्ट्रीय एकता दिवस) के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी अनुज सिंह सहित कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने सरदार वल्लभभाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी, जिलाधिकारी ने सभी अधिकारी और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस पर आधारित शपथ भी

महापौर ने झंडी दिखाकर किया रवाना

कलेक्ट्रेट सभागार में मनाई गई लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती

कुशीनगर।

स्वतंत्र भारत के वास्तुकार लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर व अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, प्रेम कुमार राय द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में स्वतंत्र भारत के वास्तुकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा (चित्र) पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई । उन्होंने कहा हम सभी को एकता ,अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए समर्पित रहना होगा तथा अपने देश /जनपद वासियों के बीच एकता का संदेश फैलाने का प्रयास करना होगा।यह स्वतंत्र भारत के वास्तुकार के रुप में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को मान्यता देने और राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने का दिन है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में लौह पुरुष की जयंती मनाई जा रही है ।आजादी के समय भारत की छोटी बड़ी रियासतों को एकता के सूत्र में पिरो कर भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा अखंड भारत का निर्माण करने का काम किए है। अखंड भारत के निर्माण के साथ साथ स्वंतत्रता संग्राम में दिए गए उनके योगदानों को याद किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आइए हम सब मिलकर यह शपथ लेते है की हम सब मिलकर देश की एकता ,अखंडता और आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देंगे। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव मिश्रा , अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रेम कुमार राय, जनपद स्तरीय अधिकारीगण , समस्त कलेक्ट्रेट सहायक एवं जनपद स्तरीय अधिकारी/ कर्मचारी उपस्थित रहे।

सरदार पटेल का सम्पूर्ण जीवन देश की एकता और अखंडता को समर्पित था-आर पी एन सिंह

पडरौना,कुशीनगर ।

देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की 150 जयंती भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे जनपद में बूथ स्तर पर धूमधाम से मनाई गई। भाजपा की ओर से सरदार बल्लभ भाई पटेल की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। दौड़ पडरौना में बावली चौक पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा से शुरू होकर सुभाष चौक पर सम्पन्न हुई। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय,सदर विधायक मनीष जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल,गौ सेवा आयोग के उपलक्ष्य अतुल सिंह,बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह की उपस्थिति में मौजूद लोगों को राष्ट्रीय एकता और नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। राज्य सभा सांसद आरपीएन सिंह ने लौह पुरुष, भारत रत्न, सरदार वल्लभभाई पटेल को नमन करते हुए कहा कि उनके अदम्य साहस, दूरदर्शिता और राष्ट्र समर्पण की भावना के कारण ही आज भारत एक शक्तिशाली और एकीकृत राष्ट्र के रूप में खड़ा है। उन्होंने कहा सरदार पटेल का सम्पूर्ण जीवन देश की एकता और अखंडता को समर्पित था।

जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि सरदार पटेल ने आजादी के बाद 560 से अधिक रियासतों को एकसूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण किया था। ऐसे महापुरुष के योगदान को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 से उनकी जयंती को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी विधानसभाओं में 10 से 20 नवंबर के बीच रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक आयोजन पर 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा के साथ नशा मुक्त भारत, एक पेड़ मां के नाम तथा आत्मनिर्भर भारत जैसे जन-जागरूकता अभियानों को भी जोड़कर समाज में सकारात्मक संदेश देने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर लक्ष्मन मिश्र,सुदर्शन पाल, रजनीकांत मणि त्रिपाठी,फूलबदन कुशवाहा, राकेश जायसवाल, सतीश चौधरी, धनजय तिवारी, सुधीर राव, विन्ध्यवासिनी श्रीवास्तव, दिवाकर मणि त्रिपाठी, मनोज जायसवाल, रमेश सिंह, विवेकानंद शुक्ल, अतुल श्रीवास्तव, बाबू नन्दन सिंह, डॉ सीमा गुप्ता, रुपम सिंह, मनीष जायसवाल बुलबुल सभी मण्डल अध्यक्षो सहित सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे।

दिल्ली का कनॉट प्लेस क्यों बना बढ़ते प्रदूषण की वजह एनडीएमसी की पार्किंग नीति पर उठे सवाल

नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में है। ऐसे में ग्रेप के दूसरे चरण के लगने के बाद नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा पार्किंग के दाम दोगुने कर दिए गए हैं। लेकिन, इसका असर प्रदूषण को कम करने की बजाय बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। कनॉट प्लेस में विभिन्न स्थानों पर पार्किंग के दाम दोगुने होने की वजह से पार्किंग में वाहन तो कम नहीं आए, लेकिन, कई लोग ऐसे भी नजर आए जो वाहन पार्किंग में खड़े करने की बजाय सड़कों पर इधर-उधर खड़े नजर आए। कनॉट प्लेस से लेकर बाबा खड़ग सिंह मार्ग, खान मार्केट के बाहर ऐसी ही स्थिति नजर आई। हालांकि, इस मामले में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने कोई जवाब नहीं दिया है। एनडीएमसी इलाके में

खास तौर पर कनॉट प्लेस में ऐसा माना जाता है कि बड़े-बड़े गाड़ियों से लोग खरीददारी के लिए आते हैं। ऐसे में उनके ऊपर चाहे पार्किंग 100 रुपये या फिर 40 रुपये इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन, कई मध्य वर्गीय लोग जब कनॉट प्लेस अपने दोस्तों से मिलने या फिर रेस्तरां में खाना खाने या फिर अन्य खरीददारी के लिए आते हैं तो वह वाहन पार्किंग में खड़ा करते हैं। उन्हें पार्किंग के दाम बढ़ने का बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए कनॉट प्लेस और बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर लोग वाहनों को पार्किंग में खड़ा करने की बजाय सड़कों पर खड़ा करके खरीददारी करते हुए नजर आए। कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में बड़ी मात्रा में वाहन सड़क पर खड़े नजर आए। कुछ लोग पांच से दस मिनट के काम के लिए अपने साथी को गाड़ी में छोड़कर काम निपटाने गए। इस दौरान वाहन चालू होने से भी प्रदूषण बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ। मंगोलपुरी से अपने दोस्त के साथ एक नामी शोरूम में अपने कपड़े बदलवाने आए ऋषभ कहते हैं कि उन्हें चूंकि अपनी एक जींस की फिटिंग सही नहीं थी इसलिए उसे बदलकर दूसरी लेना था। मुश्किल से दस मिनट का काम था इसलिए अपने दोस्त को उन्होंने बाहर सड़क पर ही खड़ा छोड़ दिया। बताया कि पार्किंग में वाहन खड़ा करते तो गाड़ी निकालने और खड़े करने में समय तो ज्यादा लगता ही बल्कि पार्किंग का शुल्क भी ज्यादा हो गया है तो वह भी देना पड़ता। इसलिए अपने दोस्त अंकित को वह गाड़ी में छोड़कर गए ताकि कोई ट्रैफिक वाला गाड़ी न उठा लें। उल्लेखनीय है कि एनडीएमसी की 125 के करीब पार्किंग है।

एनडीए का बिहार घोषणापत्र जारी, 1 करोड़ नौकरी,

महिलाओं को लखपति दीदी, राज्य के विकास का संकल्प लिया

- 1 करोड़ नौकरियों और एक वैश्विक कौशल केंद्र
- महिला सशक्तिकरण: लखपति दीदी और मिशन करोड़पति
- अत्यंत पिछड़े वर्गों (ईबीसी) का सशक्तिकरण
- किसान कल्याण: कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि
- बिहार दुग्ध एवं मत्स्य पालन मिशन
- एक्सप्रेसवे, रेल और मेट्रो विस्तार
- हवाई संपर्क : बिहार से विदेश के लिए सीधी उड़ानें
- औद्योगिक विकास और विनिर्माण को बढ़ावा
- शिक्षा: केजी से पीजी तक मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा
- गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी

पटना।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी करते हुए युवाओं और महिलाओं को लेकर बड़े वादे किए। राजग ने दावा किया कि इस राय में उसके सत्ता में आने पर हर युवा के ''सुनहरे भविष्य की गारंटी दी जाएगी, जबकि महिलाओं को ''समृद्धि और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर आगे बढ़ाया जाएगा। एनडीए के घोषणापत्र में अगले पांच वर्षों के लिए 24 प्रमुख प्रतिबद्धताओं की रूपरेखा दी गई है, जो नौकरियों, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे और कल्याण पर केंद्रित हैं। औद्योगिक विकास के लिए, एनडीए नेताओं ने सभी जिलों में कारखानों और औद्योगिक पार्कों के विकास, 100 एमएसएमई पार्कों और 50,000 छोटे उद्योगों के साथ-साथ बिहार में एक रक्षा गलियारा और एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण पार्क का वादा किया। महिलाओं के लिए राजग ने ''मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा की है, जिसके तहत महिलाओं को दो लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य की अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ाने में मदद करेगी। इसके अलावा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महत्वाकांक्षी उद्योगपतियों का समर्थन करने के लिए मिशन करोड़पति का शुभारंभ, किसानों को वार्षिक वित्तीय सहायता 6,000 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये करना, सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी और कृषि क्षेत्र को आधुनिक और टिकाऊ बनाने के लिए 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। घोषणापत्र में कहा गया है कि राजग एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियों और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। इसके लिए राय में कौशल जनगणना कराई जाएगी और कौशल आधारित रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, हर जिले में विशाल कौशल केंद्र स्थापित कर बिहार को वैश्विक कौशल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बता दें कि पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) प्रमुख जीतन राम मांझी, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति मंच (आरएलएम) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद थे। कार्यक्रम में जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा और भाजपा के वरिष्ठ संगठन महामंत्री विनोद तावड़े भी थे।अपनी पंचामृत गारंटी के तहत, एनडीए ने बिहार के गरीबों के लिए पांच प्रमुख कल्याणकारी वादे किए हैं मुफ्त राशन, प्रति परिवार 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख रुपये तक मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, 50 लाख पक्के घरों का निर्माण और पात्र परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन।

तेजस्वी का एनडीए पर डबल अटैक : घोषणापत्र को माफ़ी पत्र बताया, नीतीश की सेहत पर भी सवाल

पटना।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घोषणापत्र पर निशाना साधते हुए मांग की कि गठबंधन को जनता से माफी मांगनी चाहिए और अपने संकल्प पत्र की जगह माफी पत्र जारी करना चाहिए, क्योंकि पिछले चुनावी वादे पूरे नहीं हुए हैं और नए वादे किए गए हैं। राजद नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव शुरू होने से छह दिन पहले जारी किए गए एनडीए के संकल्प पत्र में क्या लिखा है, इस बारे में शायद सीएम को भी जानकारी नहीं है। तेजस्वी यादव ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हम कहना चाहते हैं कि हमने जो देखा है, उसके आधार पर एनडीए को एक माफी पत्र लाना चाहिए और बिहार के चौदह करोड़ लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि बीस साल शासन करने के बाद भी बिहार सबसे गरीब राज्यों में से एक है। राज्य में कारखानों और निवेश की कमी की निंदा करते हुए, राजद नेता ने कहा, न कोई कारखाना है, न कोई निवेश। सरकार सभी क्षेत्रों में विफल रही है, इसलिए उन्हें माफी पत्र लाना चाहिए था। अगर आप उनके बीस साल के झूठे मजाक को देखें, तो बीस साल तक उनके द्वारा किए गए वादे। बीस साल से वे जो भी घोषणापत्र लेकर आए हैं, उस घोषणापत्र में यह भी बताना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ राज्य में और अस्पताल बनाने के वादे की आलोचना करते हुए, यादव ने आरोप लगाया कि बुनियादी ढांचा तो बन सकता है, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स तक नहीं होंगे। यादव ने कहा कि उन्होंने कहा था कि हर जिले में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनेंगे। मेडिकल कॉलेज में न डॉक्टर है, न नर्स। न दवा है, न इलाज। कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसी हिसाब से, अगर आप देखें तो इन लोगों को माफीनामा भेजिए। इन लोगों को बिहार की 14 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए। महागठबंधन की चुनाव जीत का भरोसा जताते हुए यादव ने कहा कि जनता अब एनडीए के चाल चरित्र को समझ गई है और उनके गठबंधन को जीत दिलाएगी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ जुमला है। बिहार की जनता उनके चाल चरित्र को पहचान गई है। वे इस बार एनडीए को करारा जवाब देंगे। महागठबंधन सरकार बनाएगा। राज्य की जनता बेरोजगारी खत्म करना चाहती है।

संजय राउत की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली। शिवसेना (यूबीटी) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। तबियत बिगड़ने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतना ही नहीं वह दो महीने तक सार्वजनिक जीवन से भी दूर रहेंगे। संजय राउत ने अपने कार्यकर्ताओं को एक भावुक पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है। संजय राउत ने कहा, जय महाराष्ट्र! सभी मित्रों, परिवार और कार्यकर्ताओं से विनम्र निवेदन है, आप सभी ने हमेशा मुझ पर विश्वास किया है और मुझे प्यार दिया है, लेकिन अब अचानक पता चला है कि मेरे स्वास्थ्य में कुछ गंभीर सिरदर्द आई है। इलाज चल रहा है, मैं जल्द ही इससे उबर जाऊंगा। चिकित्सकीय सलाह के अनुसार, मुझे बाहर जाने और भीड़ में घुलने-मिलने से मना किया गया है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुझे विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा और नए साल में आपसे मिलने आऊंगा। आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे।

राज्य का दर्जा न होना केंद्रशासित प्रदेश सरकार के खराब प्रदर्शन का बहाना नहीं : उपराज्यपाल सिन्हा

जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं होने को खराब प्रदर्शन का बहाना नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि निर्वाचित सरकार के पास सभी शक्तियां हैं। सिन्हा ने यहां एसकेआईसीसी में जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा है कि पहले परिसीमन, उसके बाद विधानसभा चुनाव और फिर उचित समय पर राय का दर्जा बहाल किया जाएगा।उपराज्यपाल ने कहा, ''लेकिन कुछ लोगों को कुछ समस्याएं हैं।

जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तो यह स्पष्ट था कि चुनाव केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के लिए हो रहा है।

वे (निर्वाचित सरकार) यह बहाना नहीं बना सकते कि पूर्ण राय का दर्जा बहाल होने तक काम नहीं किया जा सकता।'' सिन्हा ने कहा कि निर्वाचित सरकार के पास सभी शक्तियां हैं और राय का दर्जा न होने के बहाने लोगों को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए करना चाहिए।

अमित शाह बोले- धारा 370 हटाकर पीएम मोदी ने पूरा किया सरदार पटेल का अधूरा संकल्प

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल को तत्कालीन कांग्रेस सरकार से वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के पहले गृह मंत्री को 41 साल की देरी के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर, केंद्रीय गृह मंत्री ने स्टैचू ऑफ यूनिटी की परिकल्पना और सरदार पटेल के सम्मान में एक भव्य स्मारक के निर्माण का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया। शाह ने कहा कि उस समय की कांग्रेस सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल को पर्याप्त सम्मान नहीं दिया। सरदार पटेल को 41 साल की देरी के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया...देश में कहीं भी न तो कोई स्मारक बनाया गया और न ही कोई स्मारक...जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तभी उन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी की परिकल्पना की और सरदार पटेल के सम्मान में एक भव्य स्मारक का निर्माण किया। इससे पहले आज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के पहले गृह मंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री ने सरदार पटेल की प्रशंसा करते हुए कहा कि आधुनिक भारत पटेल की दूरदर्शिता और प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 370 को हटाकर सरदार पटेल के संकल्प को पूरा किया है। शाह ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद, अंग्रेजों ने देश को 562 रियासतों में विभाजित करके छोड़ने का फैसला किया.

सेना प्रमुख की चेतावनी: आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बुद्धि-नैतिकता से जीते जाएंगे

नई दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को कहा कि युद्ध अब गैर-गतिज और गैर-संपर्क-होता जा रहा है और इसलिए इसके लिए ऐसी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है जिसके लिए सैन्य शक्ति, बौद्धिक कौशल और नैतिक तैयारी की आवश्यकता हो। सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने कहा कि युद्ध के तरीके लगातार बदल रहे हैं और अब ये आमने सामने नहीं लड़े जाते, इसलिए इनका सामना करने के लिए सैन्य शक्ति, बौद्धिक क्षमता और न्यायसंगत तैयारी की आवश्यकता है। सेना प्रमुख ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर मानेकशॉ सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि युवाओं को थिंक टैंक, प्रयोगशालाओं और युद्धक्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में भूमिका निभाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने भी सेना और रक्षा थिंक टैंक 'सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज' द्वारा आयोजित 'चाणक्य डिफेंस डायलॉग- यंग लीडर्स फोरम' में सैन्य अधिकारियों, छात्रों और रक्षा विशेषज्ञों को संबोधित किया। सेना प्रमुख ने अपने भाषण में युद्ध की बदलती प्रकृति और इस परिदृश्य में आवश्यक तैयारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ''युद्ध में भाग-दौड़ अब नहीं होती और यह संपर्क-रहित होता जा रहा है'' और इसलिए इसका सामना करने के लिए सैन्य शक्ति, बौद्धिक कौशल और न्यायसंगत तैयारी की आवश्यकता है।'' ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग में शामिल होती रहीं कर्नल सोफिया कुरैशी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थीं। कार्यक्रम में घोषणा की गई कि चाणक्य रक्षा संवाद 2025 नवंबर (27-28) में आयोजित किया जाएगा जिसका विषय ''सुधार से परिवर्तन सशक्त और सुरक्षित भारत' होगा।

गन्ना मूल्य का विज्ञापन अंग्रेजी अखबार में छपवाया..., अखिलेश का तंज- कितने किसान इसे पढ़ पाएंगे

लखनऊ। राजधानी लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेसवार्ता कर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर सरदार पटेल के नाम पर विश्वविद्यालय बनवाएंगे। गन्ना मूल्य पर कहा कि गन्ना मूल्य में 30 रुपये से ज्यादा की वृद्धि होनी चाहिए थी। दाम में कम से कम इतनी बढ़ोतरी करें जिसमें किसान खुशहाल हो। सपा मुखिया ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने गन्ना मूल्य और भुगतान करने का विज्ञापन अंग्रेजी अखबार में छपा। बताओ कितने किसान अंग्रेजी में यह जानकारी पढ़ पाएंगे। बहराइच की गन्ना मिल बंद हो गईं। जिम्मेदार किसानों का करोड़ों रुपया लेकर भाग गए। ये सब सरकार के पोषित लोग हैं। अब सरकार मंडियां बेचना चाहती है। एसआईआर के दूसरे चरण को लेकर अखिलेश ने कहा कि हमारी मांग है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में जाति पर एक अतिरिक्त कॉलम शामिल किया जाए। इससे जाति जनगणना कराने, बेहतर नीति निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि सरकार हमारे सुझाव पर विचार करेगी और उसे लागू करेगी। कानपुर के अखिलेश दुबे की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रहा है, उतना कभी नहीं हुआ। विकास दुबे की गाड़ी इसलिए पलटाई गई थी, कि कहीं सरकार न पलट जाए। अब

अखिलेश दुबे को बचाया जा रहा है। जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में है, उतना किसी सरकार में नहीं रहा। विश्वविद्यालय में किसे कुलपति बनाया जा रहा है, सभी को पता है।

भाजपा सरकार में इलाज कराना भगवान भरोसे

सपा मुखिया ने कहा कि सबसे अधिक असुरक्षित महिलाएं व बेटियां भाजपा सरकार में हैं। इस सरकार में दलित, पिछड़े मारे जा रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई बहुत काम नहीं हुआ। एंबुलेंस हम लोगों ने चलवाई थीं। सरकार आने पर इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। आज जब भाजपा के बड़े नेताओं को इलाज कराना होता है तो सपा सरकार में बनवाए गए मेदांता में इलाज कराने जाते हैं। इस सरकार में इलाज कराना भगवान भरोसे है। अखिलेश ने आगे कहा कि भाजपा की मूल पार्टी आरएसएस है। सरदार पटेल ने संघ पर बैन लगाया था। शर्तों पर संघ से बैन खत्म हुआ था। भाजपा हमें दूसरी चीजों में उलझाए है। अमेरिका और चीन के लिए बाजार बैने ढाल रहे हैं। कोई स्पेन बना रहा है तो कोई क्योटो। भाजपा नकारात्मकता फैला रही है। मेरठ में जो दुकानें गिराई जा रही हैं, उसका आदेश सपा सरकार में भी था। लेकिन, हमने नहीं गिराईं। भाजपा गिरा रही है।

मुख्यमंत्री को नाम बदलने का पुराना शौक

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को नाम बदलने का पुराना शौक है। यदि आपको ओसामा बिन नाम पसंद नहीं था, तो एआई से पूछते इसका हिंदी नाम बताए। यदि वह हिंदी नाम शेर सिंह बताता तो वही कर देते। धरती पर यदि किसी के साथ सबसे भेदभाव हुआ है तो वह है दलित। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संघ पर बैन की बात कही है। हम उनसे सहमत है। अखिलेश ने कहा कि जैट जीपीटी की मानें तो आरएसएस ने ऐसा वातावरण पैदा किया, जिससे नाथू राम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की। भाजपा साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पार्टी है। मैं तेजस्वी से कहूंगा को अडानी का एक-एक रुपया वापस कर दें। 10 हजार युवाओं को नौकरी देने का शपथ पत्र लें।

पटेल चाहते थे पूरा कश्मीर हमारा हो- मोदी

नेहरू ने बांटा; जो अंग्रेज नहीं कर पाए कांग्रेस ने किया, वंदे मातरम् का हिस्सा काटा

नई दिल्ली।

राष्ट्रीय एकता परेड समाप्त होते ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड स्थल तक पैदल गए और सभी उपस्थित लोगों का उत्साहपूर्वक अभिवादन किया। इस अवसर पर बोलते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने विभाजन में योगदान देने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि उसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से गुलाम मानसिकता अपनाई और इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस ने धार्मिक आधार पर वंदे मातरम के विभाजन को समाप्त किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस को न केवल अंग्रेजों से अपनी पार्टी और सत्ता विरासत में मिली, बल्कि उसने गुलामी की मानसिकता को भी आत्मसात कर लिया। कुछ ही दिनों में वंदे मातरम अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाएगा।

1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, तो वंदे मातरम विरोध में हर नागरिक की आवाज बन गया। वंदे मातरम देश की एकता और एकजुटता की आवाज बन गया। अंग्रेजों ने वंदे मातरम के जाप पर प्रतिबंध लगाने की भी कोशिश की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंग्रेज कभी सफल नहीं हुए। वंदे मातरम का जाप भारत के हर कोने में गूंजता रहा। लेकिन जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, वह कांग्रेस ने कर दिखाया। कांग्रेस ने धार्मिक आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को हटा दिया। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने समाज को बांटा और अंग्रेजों के एजेंडे को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि जिस दिन कांग्रेस ने वंदे मातरम को तोड़ने, काटने और विभाजित करने का फैसला किया, उसी दिन भारत के विभाजन की नींव रख दी गई। अगर कांग्रेस ने वह पाप न किया होता, तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती।

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर साझा किया, केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह प्रतिमा सरदार पटेल और भारत की एकता व शक्ति के प्रति उनके दृष्टिकोण को एक यादगार श्रद्धांजलि है। दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा के रूप में खड़ी यह प्रतिमा राष्ट्रीय गौरव और सरदार पटेल के सपनों को पूरा करने के सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। इससे पहले शुक्रवार को, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के प्रारंभिक वर्षों में विचारधारा, शासन और नियति को आकार देने में सरदार पटेल के योगदान को याद किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक विजुअल पोस्ट साझा किया, जिसमें उनकी दूरदर्शिता और जनसेवा की विरासत को याद किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि भारत सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। वे भारत के एकीकरण के पीछे प्रेरक शक्ति थे, जिसने हमारे राष्ट्र के प्रारंभिक वर्षों में इसके भाग्य को आकार दिया। राष्ट्रीय अखंडता, सुशासन और जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। हम एकजुट, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के उनके दृष्टिकोण को बनाए रखने के अपने सामूहिक संकल्प की भी पुष्टि करते हैं।

खड़गे की पीएम मोदी से मांग : अगर सरदार पटेल का सम्मान करते हैं तो आरएसएस पर बैन लगाएं

नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत में कानून-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आरएसएस जिम्मेदार है और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचमुच सरदार वल्लभभाई पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं, तो उन्हें आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लेना चाहिए। खड़गे ने कहा कि ये मेरे निजी विचार हैं और मैं खुले तौर पर कहता हूं कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री वल्लभभाई पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं, तो ऐसा होना चाहिए। देश में सभी बुराइयों और कानून-व्यवस्था की सभी समस्याएँ भाजपा और आरएसएस की देन हैं। सरदार पटेल के बारे में बोलते हुए, खड़गे ने कहा कि उन्होंने भारत की लौह महिला इंदिरा गांधी के साथ मिलकर देश की एकता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने सरदार पटेल द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखे पत्र का स्मरण किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरह से आरएसएस ने गांधीजी की मृत्यु पर खुशी मनाई थी, उसे देखते हुए उन पर प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने जोर देकर कहा कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस ने मिठाइयाँ बाँटी थीं। खड़गे ने कहा कि पटेल ने एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि जिस तरह से आरएसएस के लोगों ने गांधीजी की मृत्यु पर खुशी मनाई थी, उसे देखते हुए उन पर प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने यह पत्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा था...संघ के लोगों के भाषण ज़हर से भरे होते हैं; उन्होंने गांधीजी की हत्या के बाद मिठाइयाँ बाँटीं। उन्होंने यह पत्र गोलवलकर को भी लिखा था। इससे पहले, कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने राय के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी मंदिरों में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने का आग्रह किया था। उन्होंने संगठन पर युवाओं का ब्रेनवॉश- करने और संविधान के विरुद्ध दर्शन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था।